RAJYA SABHA

Tuesday, the 23rd March, 1993/2nd Chaitra 1915 (SAKA)

The House met at eleven of the clock, *Mr. Chairman* in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सूत की आवश्यकता तथा उत्पादन

*381. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री राम जेठमलानी† :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में हथकरघा, विद्युत करघा और कपड़ा मिलों जैसे विभिन्न क्षेत्रों की सूत की वार्षिक आवश्यकता के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया है ।

(ख) यदि हां, तो देश में किस-किस किस्म के कितने-कितने सूत की आवश्यकता होती है और

(ग) सूत के उत्पादन के लिए कितनी कपास की आवश्यकता होती है और देश की आवश्यकतानुसार कपास से सूत तैयार करने के लिए वर्तमान व्यवस्था क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) :—(क) से (ग) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) विभिन्न क्षेत्रों द्वारा कपड़े के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए हथ-करघा, विद्युतकरघा तथा मिल क्षेत्र में यार्न की जरूरतों का क्रमशः लगभग 400 मिलियन कि०ग्रा०, 1170 मिलियन कि०ग्रा० तथा 330 मिलियन कि० ग्रा० होने का अनुमान है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूती स्पन यार्न, ब्लैंडिड तथा शत-प्रतिशत गैर-सूती यार्न का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

स्पन यार्न का उत्पादन :

(मात्रा मिलियन कि० ग्राम में)

वर्ष	सूती यार्न	ब्लैंडिड यार्न	शत प्रतिशत गैर-सूती यार्न	कुल
1990–91	1510	207	107	1824
1991–92	1450	234	122	1806
1992–93 (अनुमानित)	1432	246	146	1820

† सभा में यह प्रश्न श्री राम जेठमलानी द्वारा पूछा गया ।

इसके अतिरिक्त पिछले तीन वर्षों के दौरान फिलामेंट यार्न, रेशमी यार्न तथा ऊनी यार्न का उत्पादन निम्न प्रकार था :—

(मात्रा मिलियन कि० ग्राम में)

वर्ष	फिलामेंट यार्न	रेशमी यार्न	ऊनी यार्न (ब्रस्टिड तथा गैर-ब्रस्टिड)
1990–91	276	12	108
1991–92	291	11.6	117
1992–93 (अनुमानित)	333	14	128

(ग) वर्ष 1991–92 के दौरान कपास की खपत वर्ष 1992–93 के दौरान 105 लाख गांठ के अनुमनित स्तर की तुलना में 102 लाख गांठ है। 31 दिसम्बर, 1992 की स्थिति अनुसार (देश में 1137 मिलें हैं (866 मिलें कताई मिलें तथा 271 मिलें मिश्रित मिलें हैं) जो कि कपास से यार्न का उत्पादन करती है।

SHRI RAM JETHMALANI : Sir, my first supplementary question is : Has the hon. Minister taken note of the very steep decline in the production of cotton yarn ? In 1991 it was 1510 million kgms. In the next year it has been reduced by 60 million kgms and in the year 1992-93 the decline is another 118 million kgms. Has this decline been investigated ? Have you found out the impact of this on our export performance and on our export contracts ? Are any steps contemplated to prevent this decline ?

श्री जी० वेंकटस्वामी : सभापति जी, मैंने माननीय सदस्यों को पूरी फिगर्ज सप्लाई की है। हमारे यहां जो यार्न प्रोडक्शन होता है वह देश के लिए जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसी तरह से मैंने उनको फिगर्ज भी दी है कि हैंडलूम के लिए कितना, पावरलूम के लिए कितना और मिल्स के लिए कितना जरूरत है। यह पूरे आंकड़े मैंने माननीय सदस्य को सप्लाई किये हैं। उसके बाद जो बचा है उसको एक्सपोर्ट के लिए रखा है। एक्सपोर्ट करने के बावजूद हमारे पास यार्न सरप्लस मौजूद हैं। इसके इलावा यदि कोई इनफारमेशन चाहते हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूं।

SHRI RAM JETHMALANI : Sir, the second supplementary is this. They have framed a policy about production of hank yarn in the handloom sector and they have the National Textile Corporation—121 mills—in operation. Under the statutory policy framed they are under an obligation to produce 50 per cent of their marketable capacity for hank yarn and 85 per cent of the 50 per cent is supposed to be 40 strands and over. Now I understand and it is widely reported and it was a matter of serious debate, that when the Ministers met recently in a conference about this policy, everybody said that these 121 mills had a shortfall this year, an alarming shortfall of 10 millions against 43 millions targeted. The Minister seems to be expressing no concern at all. Why is the hank yarn—when you have fixed a target of nearly 43 millions—production only 10 millions ? Surely, this is not a mater which is without any concern and the Minister seems to be suggest-

ing that everything is hunky-dory. First of all, is that true ? Have you taken any steps, because it is a criminal offence as these units did not manufacture according to this policy which is statutory ? They have to be prosecuted. Have you thought of prosecution ? The private sector in this situation is the only sector which has surpassed the targets. So, are you thinking of privatisation ? Are you thinking of prosecuting these persons so that full target is achieved ?

श्री जी० वेंकट स्वामी : सभापति जी, यह सही है कि हैंक यार्न की सप्लाई जो करनी है, सारी मिल्स पूरी तरह से नहीं कर रही हैं। यह बिल्कुल सही बात है । मगर उसके खिलाफ हम लोगों ने चार सौ से ज्यादा लोगों को प्रोसीक्यूट किया है । इस बात की हम कोशिश कर रहे हैं । बात यह है कि हैंडलूम वीवर्स की कंडीशन देश के अंदर बहुत खराब है। उनको हैंक यार्न पहुंचाने के लिए जो तरीका हमने शुरू किया था, जो 10 लाख मिलियन केजी की हैंक यार्न सप्लाई करने की हमारी स्कीम थी उस 10 मिलियन केजी स्कीम में हम लोगों ने 1.6 मिलियन केजी हैंक यार्न हैंडलूम वीवर्स को सप्लाई किया है । बहुत ही कम हुआ है । इसके लिए हम नयी योजना बना रहे हैं क्योंकि हैंडलूम वीवर्स बहुत ही परेशान हैं कि यार्न न मिलने की वजह से । उसी का नतीजा है कि हैंडलूम वीवर्स दिन ब दिन बिलो पावर्टी आ रहे हैं । इसके लिए हमने सारे देश के हैंडलूम वीवर्स की एक कान्फ्रेंस रखी और उनकी क्या मुश्किलात हैं उसको जानने की कोशिश की । फिर उसके बाद सारे देश के हैंडलूम मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस की और उसमें एक प्रोग्राम बनाया कि किस तरह से हैंक यार्न उन लोगों को पहुंचाया जाए । उसके लिए चंद स्कीमें हमने तैयार की हैं । वे स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को भी दी है । हैंक यार्न जब तक उनको नहीं प गा तब तक हैंडलूम वीवर्स को बहुत तकलीफ होगी । मैं आनरेबल मेम्बर्स को यह बता देना चाहता हूं कि हम करीब में हैंडलूम वीवर्स की हर तरह की मुश्किलात को दूर करते हुए उन्हें हैंक यार्न पहुंचाने की कोशिश करेंगे ।

SHRI RAM JETHMALANI : I am sorry that the hon. Minister doesn't answer my question. You have got the Finance Ministry's new policy. You have got the Finance Minister sitting here. Why don't you follow his advice and dispose these things of to the private sector ? The private sector has produced more than you have targeted for. If your units are inefficient, then follow the policy of the Finance Ministry. You don't seem to be thinking in tandem at all. Have you thought of privatisation as a measure ? (*Interruptions*) This is not the policy. The policy is to privatise. Are you thinking of that at all ? Is it true that the private sector has surpassed the target ?

SHRI G. VENKAT SWAMY : Not at all, Sir.

सारे प्राइवेट सेक्टर अगर किये हैं, बोलते हैं तो आनरेबुल मेम्बर गलतफहमी में हैं । वे लोग अगर सही तरीके से करते तो हैंक यार्न मिलने में मुश्किल नहीं होती । हम कोशिश कर रहे हैं उस टारगेट पर पहुंचने के लिए उनसे सही मायनों में 50 परसेंट आब्लीगेशन को पूरा करने में ।

SHRI H. HANUMANTHAPPA : Sir, the Minister is thinking of yarn but this raw material is sandwiched between the Commerce Ministry, the Agriculture Ministry and the Textile Ministry. Has he taken care of that ? Farmers are not thinking of producing cotton in the next year. Twenty-five lakh bales of cotton are lying idle and the price has come down from Rs. 2600 to Rs. 800. Is the Minister thinking of giving some inducement to the farmers to take up production of cotton so that he can take care of yarn and handloom

subsequently ? Now, the farmers are in a dilemma whether to go in for cotton or not. I don't think that next year the Minister will get the amount of cotton that he is expecting unless the cotton which is lying idle is exported and freight is also taken care of. While taking permission for the export of cotton, the interests of the farmers are to be taken care of. Farmers have already sold the produce at a throw away price, Rs. 800 or Rs. 900. Now, cotton is in the middlemen's hands and they are pressurising the Government for exporting it. So, they will get the benefit. How is the Government going to take care of the farmers and induce them to take to cotton next year in view of the prevailing situation ?

श्री जी० वेंकट स्वामी : सभापति जी, बात यह है कि लास्ट इयर सही है कि काटन का प्राइस बहुत ज्यादा था । इस साल भी ग्रोअर्स ने बहुत सारा काटन प्रोडयूस किया है । काटन एडवाईसरी बोर्ड जो है उन लोगों ने रिकमेंड किया है कि 5 लाख बेल्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए । 10 लाख बेल अलावा फिरप्रेशर आया किसानों से कि रेट गिरता जा रहा है ।

सपोर्ट प्राइस से हमको बैलेंस करना पड़ता है कि हैंडलूम वीवर्ज का भी जो है यार्न रेट न बढ़े और दूसरी तरफ किसानों को भी इसका कोई नुकसान न पहुंचे । तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने और पांच लाख बेल का एक्सपोर्ट करने का परमिशन दिया है और इस वक्त रेट जो है सपोर्ट प्राइस से 200 से लेकर 400 तक ऊंचा चल रहा है । किसान बहुत खुश है कि हमने यह पांच लाख बेल एक्सपोर्ट करने से और उनका रेट बढ़ा है और इस से किसान को अच्छा प्राइस मिल रहा है ।

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA : Sir, I want to bring to the notice of the Minister that Punjab produces 24% of cotton in the country but there is no spinning unit available to increase the production of yarn. Will the Minister of Textiles take up this matter with the Finance Ministry because the Finance Ministry is not lending financial help to put up a spinning industry in Punjab ? Will the Minister assure us that he will take up the matter with the Finance Ministry so that a spinning mill can be established in Punjab ? Actually Punjab produces 24% of the cotton.

श्री जी० वेंकट स्वामी : पंजाब में तो काटन का प्राइस बहुत ही अच्छा जा रहा है । खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूं आज का प्राइस 1080 रुपया है पंजाब काटन का प्राइस जो सपोर्ट प्राइस 700 चिल्लर है । मैं आनरेबल मैम्बर का ... (**व्यवधान**) पिछले साल 1500 नहीं उससे भी ज्यादा था । उसका वह जो ज्यादा हुआ उसके बहुत सारे कारण हैं । मैं अब इस वक्त उसका जवाब नहीं बोलना चाहता हूं । मगर अभी आनरेबल मेंबर ने जो पूछा है काटन हम पंजाब में पैदा करते हैं और वहां पर स्पिनिंग मिल नहीं है, उसके लिए फाईव ईयर प्लान में हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर भी एक स्पिनिंग मिल लाने का ऐसा सोचा है । मैं नेक्स्ट इसके बारे में जो भी योजना में आएगा उसको बताऊंगा ।

श्री छोटू भाई पटेल : सर, हम इतिहास देखें तो हैंडलूम वीवर्ज की काफी जानें आन्ध्र प्रदेश में और देश के अन्य भागों में गई हैं क्योंकि हैंडलूम वीवर्ज को जो हैंकयार्न मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है और जो मिल हैं जो 50 परसेंट हैंकयार्न बनाना जरूरी है वह नहीं बनाती हैं, तो इन मिलों को आप क्या शिक्षा देने जा रहे हैं ? नं० दो एग्रीकल्चर कामर्स, फाइनांस और टैक्सटाइल इन चारों मिनिस्ट्रीज ने मिलकर कोई प्रीहेंसिव एक्शन प्लान बनाया ? अगर बनाया है तो इसका ब्यौरा क्या है ?

श्री जी० वेंकट स्वामी : मैं आलरेडी इसका जवाब दे चुका हूं ।

श्री एस० एस० सुरजेवाला : सभापति महोदय, अभी मंत्री महोदय ने यह बताया कि काटन की प्राइस जो है वह सपोर्ट प्राइस से ऊपर है और किसान बहुत खुश है । मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह ठीक है कि पिछले साल काटन की प्राइस 15–16 सौ रुपए क्विंटल थी और उससे पिछले सालों में भी काटन की प्राइस हमेशा आज की प्राइस से बहुत ज्यादा रही है जबकि इस साल काटन की प्राइस हरियाणा में और सर, पंजाब में भी, मुझको नहीं पता 1100 और 1080 रुपये इन्होंने बताया है कि आज की कीमत है, मुझको नहीं पता कि वह कौन सी जगह है, लेकिन हरियाणा में आज काटन की कीमत 900 और 950 रुपये से ज्यादा नहीं है और 850 रुपये तक भी काटन बिकी है । वहां पिछले सालों मे पहले काटन जो था वह गुजरात में और दूसरे इलाकों में होता था, लेकिन ग्रेजुयली काटन का एरिया जो बढ़िया काटन है, लांग स्टैपल काटन है वह आज हरियाणा के इन जिलों में सिरसा, हिसार, जींद, रोहतक, सोनीपत इन जिलों में होती है, तो क्या मंत्री महोदय किसानों की मदद करने के लिए हरियाणा में कोई ऐसी योजना बनायेंगे, धागा मिल और दूसरे मिल लगाने की और काटन की और ज्यादा एक्सपोर्ट करके किसानों को इस डिजास्टर से बचायेंगे, जो आज उनको डिसट्रेस सेल करनी पड़ी और काटन का उनको पिछले साल का बराबर का रेट दिलवायेंगे ?

श्री जी वेंकट स्वामी : सभापति जी, पिछले साल का काटन रेट तो बहुत ही ज्यादा था, वह आप सब को मालूम है । मगर इस साल जो सपोर्ट प्राइस है उससे ज्यादा किसान को दिलाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं । मैं आनरेबल मैंबर को विश्वास दिलाता हूं कभी भी सपोर्ट प्राइस से नीचे नहीं आएगी, उससे 300–400 रुपये ज्यादा रहेगी और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि प्राइसेस गिर न पाएं और किसान को किसी किस्म की तकलीफ न हो ।

श्री एस० एस० सुरजेवाला : क्या सपोर्ट प्राइस को बढ़ायेंगे ?

श्री जी० वेंकट स्वामी : उसके लिए मैं, उसकी एक कमेटी होती है सभापति जी, और सारे देश के लिए वह लोग देखते हैं और देख कर उसको तय करते हैं ।

श्री भूपेन्द्र सिंह मान : सभापति जी, इस वक्त काटन को किसान खुद जिन्निंग नहीं कर सकता, उसको लाइसेंस लेना पड़ता है और दूसरा अगर किसान एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई खेत में कपास उगाए तो क्या उसको जहां वह चाहे बेच सकता है, एक्सपोर्ट के लिए अगर वह पैदा करता है ? मेरे प्वायंटेड सवाल हैं इसलिए इन दोनों का मुझे प्वायंटेड जवाब दें कि क्या किसान अपनी खुद जिन्निंग मिल लगाकर लाइसेंस कोटे के रिश्वत देने के बिना अपनी कपास को प्रोसैस कर सकता है और दूसरा अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करता है तो क्या उसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत यह देंगे ?

श्री जी० वेंकट स्वामी : सभापति जी, मैंने कहा कि आनरेबल मैम्बर को इससे पहले भी मैंने जवाब दिया कि काटन प्राइसेस को हैंडलूम वीवर्स के ऊपर असर न पड़े ज्यादा प्राइस अगर बढ़ाना है तो एक्सपोर्ट करना पड़ता है, सभापति जी, अगर पूरी तरह से काटन

को हम एक्सपोर्ट करें और हैंडलूम के लिए या पावर लूम के लिए और मिल्स के लिए अगर काटन नहीं रहे, प्राइसेस बढ़ जाएं तो हमारे लिए कंट्री के लिए बड़े तकलीफ देंगे तो मैं आनरेबल मैंबर को यह बताना चाहता हूं कि अब तक कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काटन पैदा करके एक्सपोर्ट करने की खास तौर से इजाजत देने की कोई ऐसी स्कीम नहीं है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह मान : किसान अगर खुद उसको प्रोसैस करना चाहे तो लाइसेंस कोटा परमिट की, रिश्वत देने के बिना यह लेने की एक किसान को इजाजत होगी कि लाइसेंस के बिना वह सब कुछ कर सके ।

श्री जी० वेंकट स्वामी : यह एक नया इन्फार्मेशन है, सभापति जी, रिश्वत के साथ लाइसेंस मिलने की बात मेरे को पहली मर्तबा है, क्योंकि मुझे 2 महीने हुए हैं मिनिस्टर बने हुए, लाइसेंस रिश्वत के साथ मिलता है यह मुझे नहीं मालूम । अगर ऐसी कुछ बात है तो मैं जरूर उसके ऊपर गौर करूंगा ।

MR. CHAIRMAN : Yes, Mr. Mentay Padmanbham.

SHRI MENTAY PADMANABHAM : Sir, two issues are involved in this. One is to give remunerative prices to the cotton growers and the other issue is to supply hank yarn to the handloom sector at a reasonable price. So, these two are rather irreconcilable issues.

SHRI NARAYANASAMY : It is a continuing issue.

SHRI MENTAY PADMANABHAM : To get over this problem, the Government had, over a period, subsidised the yarn supplies to the weavers. This subsidised supply to the weavers is not working well and is full of loop-holes. I would like to know from the honourable Minister whether he is goining to revise this subsidised supply of yarn to the handloom sector, particularly to ward off lack of work for the handloom weavers and to provide more work to the weavers. I would like to know whether he will revise this subsidised system of supplying hank yarn to the handloom weavers. This is an important question.

श्री जी० वेंकट स्वामी : सभापति जी, पहले यह हैंक यार्न सप्लाई के लिए ट्रांसपोर्ट चार्जेज वगैरह के लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से 5 परसेंट सबसिडी दी जाती थी और हैंक यार्न पूरी तरह से वीवर्स को सप्लाई होता था, मगर 2 परसेंट होने की वजह से, मैं फिगर अभी तक बता चुका हूं दो वर्ष पूर्व जिस तरह से हैंक यार्न पूरी तरह से सप्लाई हुआ इस साल नहीं हो सका क्योंकि 5 परसेंट से 2 परसेंट सबसिडी किया गया है । ट्रांसपोर्ट चार्जेज और बहुत सारी चीजें हैं एक्सपेंडीचर हैं, तो हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं, फाईनांस मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं, मेरी रेक्विजीशन गई है इनस्टैड आफ 2 परसेंट 5 परसेंट अगर किया जाए तो हैंक यार्न पूरी तरह से इस साल वीवर्ज को हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे ।

Price of Consumer Items

*382. SHRIMATI VEENA VERMA :†
SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the recent increase in support prices of wheat, rice and other products contributed to the rise in prices of other consumer items also like soaps,

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Veena Verma.